

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

विषय:-मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख/उपचार की व्यवस्था हेतु कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3046/स0क0/लेखा-बजट/पुर्न0-प्रस्ताव/2017-18 दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु ₹ 21.30 (रुपये इक्कीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल रसाही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 दिसम्बर, 2017

विषय:-मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख/उपचार की व्यवस्था हेतु कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3046/स0क0/लेखा-बजट/पुर्न0-प्रस्ताव/2017-18 दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु ₹ 21.30 (रुपये इक्कीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेंजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग या अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित

8

किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में भित्तव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235-02-107-07 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
 8. उक्त धनराशि वित्त विभाग के आ0शा0संख्या-1342/XXVII(1)/17 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में पुनर्विनियोग अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या- R1712150134 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के द्वारा किया गया है तथा धनराशि का आवंटन अनुदान संख्या-15 के अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या S1712150251 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।
 9. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या-638/XVII-2/2017-01(म0क0)/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।
- संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,


(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 9/6 /XVII-2/2017-01(म0क0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जे0पी0 बेरी)
अनु सचिव।

पत्र संख्या - 916
प्रदान संख्या - 015

/XVII-2/17-01(M.K.)2016

अलोटमेंट आई डी - 51712150251

आवंटन पत्र दिनांक - 26 Dec 2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

सेवा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
 107 - स्वेच्छिक संगठनों को सहायता
 07 - मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/ महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वेच्छिक संगठनों को सहायता
 00 - -

मांगक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	2000000	2130000	4130000
	2000000	2130000	4130000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

2130000



उत्तराखण्ड शासन
(द्वितीय वर्ष 2016-2017)
बी.एस. - 09

कलोनियल आईडी - R1712150134
दिनांक - 15-Dec-2017

(In Rupees)

क्र. सं.	विवरण (1)	मानक दरदार व्यक्तिगत दर	विशेष दर कटौती दर	समावेशित दर	समावेशित दर	कुल दर	कुल दर	कुल दर
1	04 - चक्र कर	0	0	30000	20 - सहभागीकरण/सहायता/सहायता	2130000	4130000	0
2	05 - सामान्य सेवा कर	0	0	50000	02 - सामान्य सेवा	0	0	0
3	07 - नगर कर	0	0	250000	107 - स्थानीय सेवाओं को सहायता	0	0	0
4	08 - कार्यालय भवन	0	0	50000	07 - मानविकीय सेवाओं को सहायता	0	0	0
5	09 - विद्युत दर	0	0	50000	00 -	0	0	0
6	10 - नगर/नगर	0	0	30000	(Voted)	0	0	0
7	11 - निजामती और फार्मों का	0	0	50000		0	0	0
8	12 - कार्यालय फार्मों पर उपकर	0	0	100000		0	0	0
9	13 - टैक्सों पर दर	0	0	30000		0	0	0
10	17 - निराशा, उपभुक्त और कर	0	0	200000		0	0	0
11	18 - प्रशासन	0	0	10000		0	0	0
12	28 - संपत्ति और संपत्ति/उपकर	0	0	200000		0	0	0
13	27 - निजामती कर प्रशिक्षण	0	0	100000		0	0	0
14	34 - सामान्य और सामान्य	0	0	500000		0	0	0
15	44 - नगर कर	0	0	300000		0	0	0
16	45 - नगर कर	0	0	30000		0	0	0
17	46 - नगर कर	0	0	100000		0	0	0
18	47 - नगर कर	0	0	50000		0	0	0

